ए-45011/04/2023-समन्वय II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली, 04 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को नवंबर, 2023 माह में आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के मासिक सारांश के अगोपनीय भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सु. सामंत

(सुश्रुत सामंत)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 2309-5244

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एंड सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी 20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-II)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्ति और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (निवेश)/संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (वित्त मंत्री)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2023

ए-45011/04/2023-समन्वय II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

विषय: नवंबर, 2023 माह में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का मासिक सारांश

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

व्यापक आर्थिक पर्यवलोकन:

वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) की दूसरी तिमाही (दूसरी तिमाही) के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 30 नवंबर को जारी किया गया। दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत अनुमानित है, जो आरबीआई के 6.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान और व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा 6.8 प्रतिशत के औसत अनुमान से अधिक है। पहली छमाही (पहली तिमाही+दूसरी तिमाही) में वृद्धि का अनुमान 7.7 प्रतिशत है, जो 2023 के अप्रैल-सितंबर की अवधि के दौरान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। **प्रभावशाली विकास प्रदर्शन को देखते हुए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत से संशोधित करके 7.0 प्रतिशत कर दिया है।** हालाँकि, वित्त वर्ष 24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 5.4 प्रतिशत पर बना हुआ है। यह इस आकलन को दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब **गैर-मुद्रास्फीतिकारी विकास पथ** पर है। हालाँकि, आरबीआई सतर्क बना हुआ है और उसने रेपो और अन्य सभी दरों को अपरिवर्तित रखा है।

दूसरी तिमाही में जीडीपी अनुमान विकास में निजी खपत और सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के निरंतर योगदान की पुष्टि करता है। एक ओर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दरों में गिरावट की प्रवृत्ति निजी खपत को मजबूती प्रदान कर रही है, तो दूसरी ओर सरकारी पूंजीगत व्यय, जिसमें पहली छमाही में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ने जीएफसीएफ को सुदृढ़ करना जारी रखा है। मंद वैश्विक विकास ने भारत के व्यापारिक निर्यात को धीमा कर दिया है, हालांकि सेवा निर्यात, जो भारत के बढ़ते तुलनात्मक लाभ को दर्शाता है, मजबूत बना हुआ है। भारत के बढ़ते आय स्तर के कारण आयात तेजी से बढ़ा है, लेकिन इससे वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष व्यापार घाटा कुछ हद तक बढ़ गया है।

मांग में वृद्धि संबंधी इन कारकों ने उत्पादन और निर्माण दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया है, जिन्होंने दूसरी तिमाही में उच्च विकास दर दर्ज की है। परिवारों द्वारा अचल संपत्ति की बढ़ती मांग निर्माण क्षेत्र में वृद्धि में सहायक है। हालाँकि, दूसरी तिमाही में व्यापार, होटल और परिवहन सेवाओं में थोड़ी नरमी आई है, तथापि वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं की वृद्धि सराहनीय बनी हुई है। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में शहरी बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में 6.6 प्रतिशत हो गई है, जिसने विकास को अधिक समावेशी बना दिया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की नवीनतम रिलीज में अनुमान लगाया गया है कि दूसरी तिमाही में बेरोजगारी दर पहली तिमाही के समान 6.6 प्रतिशत रहेगी।

वित्त वर्ष 24 के पहले सात महीनों में राजकोषीय घाटा बजटीय स्तर के केवल 45 प्रतिशत का उपयोग करके व्यापक आर्थिक स्थिरता में सहायता प्रदान करता रहा है। यह न केवल पिछले वर्ष की तुलना

में कम है, बल्कि पिछले पांच वर्षों की इसी अवधि के औसत से भी कम है। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर संग्रह (पहले सात महीनों में क्रमशः 17.4 प्रतिशत और 31.1 प्रतिशत की वृद्धि) के साथ-साथ जीएसटी मासिक संग्रह (वित्त वर्ष 24 में छठी बार अक्टूबर 2023 में ₹ 1.6 लाख करोड़ को पार) में उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि देखी गयी है जिसने राजकोषीय अनुशासन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

व्यापक आर्थिक स्थिरता का एक अन्य स्तंभ, चालू खाता घाटा (सीएडी) भी सहज रहा। दिसंबर में आरबीआई के व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण जारी किया गया था जो यह बताता है कि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के सापेक्ष सीएडी 1.7 प्रतिशत होगा। सीएडी को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त होगा। 1 दिसंबर 2023 को विदेशी मुद्रा भंडार 604 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 3 नवंबर 2023 को 591 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ गया है।

इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास परिदृश्य और व्यापक आर्थिक स्थिरता की स्थिति अच्छी बनी हुई है।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) निम्नलिखित जी20 कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क. वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालयों के सहयोग से 6 नवंबर, 2023 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में "सुदृढ़, सतत, संतुलित और समावेशी विकास" पर एक सेमिनार की मेजबानी की। सेमिनार का आयोजन जी20 नई दिल्ली में लीडर्स घोषणा के परिणामों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए किया गया था, जिसमें तीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था: "विकास के लिए व्यापार को अनलॉक करना", "काम के भविष्य के लिए तैयारी" और "मजबूत और सतत विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ: आगे का रास्ता"। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की माननीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। इसके बाद क्रमशः व्यापार, कार्य के भविष्य और वित्तीय समावेशन पर तीन पैनल चर्चाएँ हुईं।

ख. वित्त मंत्रालय ने 15 नवंबर, 2023 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र के सहयोग से "21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों" पर एक सेमिनार की मेजबानी की। सेमिनार का आयोजन जी20 नई दिल्ली में नेताओं की घोषणा के परिणामों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए किया गया था जो मुख्यत: दो विषयों पर केंद्रित हैं: "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार" और "वैश्विक ऋण जोखिमों का प्रबंधन"। उद्घाटन सत्र के दौरान, सचिव (ईए) ने प्रारंभिक टिप्पणी की और श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने आधार व्याख्यान दिया। क्रमशः दो पैनल चर्चाएँ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार और वैश्विक ऋण जोखिम के प्रबंधन पर आयोजित की गईं।

ग. सेकण्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की दूसरा बैठक 17 नवंबर, 2023 को "सभी के विकास, सभी के विश्वास के लिए एक साथ" के व्यापक विषय के तहत आयोजित की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिणी विश्व के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत की अध्यक्षता के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्रियों का समर्पित सत्र वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सचिव (ईए) ने की थी और इसका मुख्य विषय "जन-केंद्रित विकास का वित्तपोषण" था। सत्र के दौरान, ग्लोबल साउथ के सदस्यों ने सतत विकास लक्ष्यों और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

समय पर और पर्याप्त वित्त जुटाने, अंतिम सिरे तक वित्तीय समावेशन और विकास के लिए जन-केंद्रित वित्तपोषण दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की सुविधा के लिए जी20 जैसे वैश्विक मंचों के महत्व पर जोर दिया।

घ. जी-20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (आईडब्ल्यूजी) के परिणामों से सीखने के लिए 29 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के साथ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा "शहरी अवसंरचना के विकास के लिए निजी वित्त का लाभ उठाना" विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ङ. वित्त मंत्रालय द्वारा 30 नवंबर, 2023 को सुषमा स्वराज भवन में सतत वित्त एजेंडा को आगे बढ़ाने पर जी20 राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय कार्यशाला में सचिव (ईए) और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री बिबेक देबरॉय ने विशेष टिप्पणी की। कार्यशाला में आरबीआई, सिडबी, आईबीए, एमओएफ और शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों, कई निजी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।

(ii) निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आधिकारिक स्तर पर आयोजित की गई/उनमें सहभागिता की गईं:

क. 03 नवंबर, 2023 को बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण के प्रस्तावों पर विचार के लिए डीईए स्क्रीनिंग समिति की 143वीं बैठक आयोजित की गई थी।

ख. 29 से 30 नवंबर, 2023 तक एआईआईबी निदेशक मंडल की बजट, मानव संसाधन और क्षतिपूर्ति बैठक आभासी रूप से हुई।

ग. 1 नवंबर, 2023 को भारत-जर्मन वार्षिक वार्ता बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, जर्मन पक्ष ने 1047.4 मिलियन यूरो की नई वित्तीय प्रतिबद्धताएं की।

घ. 29वीं लेखापरीक्षा, जोखिम और अनुपालन समिति की आभासी बैठक 27 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

ङ. एनडीबी के निदेशक मंडल की 42वीं आभासी बैठक 28 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

च. एनडीबी की बजट, मानव संसाधन और क्षतिपूर्ति समिति की 25वीं आभासी बैठक 27 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

छ. 21 नवंबर, 2023 को अनुमोदन समिति की 12वीं बैठक में आईआईपीडीएफ योजना के तहत पीपीपी मोड पर 2.23 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए लेनदेन सलाहकार (टीए) को नियुक्त करने के लिए ग्रेटर विशाखापत्तनम स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीवीएससीसीएल), आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

ज. 23 नवंबर, 2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की 13वीं बैठक में छात्रों और संकायों के लिए फिनटेक उत्कृष्टता केंद्र, आवास और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए लेनदेन सलाहकार (टीए) को नियुक्त करने के लिए आईआईएम मुंबई के प्रस्ताव को आईआईपीडीएफ योजना के तहत पीपीपी मोड पर 4.0356 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई।

झ. सचिव डीईए ने 2 और 22 नवंबर, 2023 को भारत-यूके द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) चर्चा/वार्ता का नेतृत्व किया।

ञ. भारत-ऑस्ट्रेलिया बीआईटी वार्ता का 9वां दौर 2 और 3 नवंबर, 2023 को डीवीसी के माध्यम से आयोजित किया गया था।

ट. भारत-पेरू निवेश आभासी वार्ता 3 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई

ठ. भारत-रूस बीआईटी वार्ता का 13वां दौर 9 नवंबर, 2023 को डीवीसी के माध्यम से आयोजित किया गया था।

ड. भारत-यूएई बीआईटी वार्ता का 16वां दौर 22 और 23 नवंबर, 2023 को डीवीसी के माध्यम से आयोजित किया गया था।

ढ. भारत-यूएई वार्ता का 17वां दौर 29 और 30 नवंबर 2023 को डीवीसी के माध्यम से आयोजित किया गया था।

ण. साझेदार देशों को ऋण सुविधा (एलओसी) पर अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) 22 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

(iii) निम्नलिखित ऋण समझौतों पर बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ हस्ताक्षर किए गए:

क. उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, सेवा प्रदान करने में सुधार और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए शहरी सुधार एजेंडे का समर्थन करने के लिए 13 नवंबर 2023 को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नीति आधारित ऋण।

ख. एमएनआरई के परियोजना प्रस्ताव अर्थात् 'फर्स्ट लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन' के लिए 10 नवंबर, 2023 को विश्व बैंक से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और वित्तीय सहायता।

ग. हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर 6 नवंबर, 2023 को हस्ताक्षर किए गए।

(iv) निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड में चर्चा की गई:

- भारत की 2023 अनुच्छेद IV की रिपोर्ट।

(v) इस माह के दौरान निम्नलिखित अधिसूचनाएँ जारी की गईं:

क. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर ₹ 75/- मूल्य का स्मारक सिक्का।

ख. संत मीरा बाई की 525वीं जयंती के अवसर पर ₹ 525/- मूल्य का स्मारक सिक्का।

ग. सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे के प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर ₹ 75/- मूल्य का स्मारक सिक्का।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या : 06
विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में : 14

6. **नवंबर, 2023 के दौरान डीईए की स्क्रीनिंग समिति द्वारा मंजूर की गई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या:** छह (06) परियोजनाएं, नामत: 1040 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल 3 ऋण और 3 तकनीकी सहायता प्रस्ताव।

7. **नवंबर, 2023 के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित वीजीएफ परियोजनाओं की संख्या:** एक (01) परियोजना, जिसकी परियोजना लागत ₹7055 करोड़ और वीजीएफ ₹ 1950 करोड़ है।

8. **नवंबर, 2023 के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित पीपीपीएसी परियोजनाओं की संख्या:** तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट की एक (01) पीपीपी परियोजना, जिसकी परियोजना लागत ₹7055 करोड़ है।

9. **नवंबर, 2023 के दौरान भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत अनुशंसित एलओसी:** मंगोलिया को 412 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक (01) नई एलओसी।